अध्याय 6

बच्चों का पुनर्वास

विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियों (एसएए) द्वारा बच्चों को गोद लेने के लिए स्वतंत्र घोषित करने वाले बाल अध्ययन प्रतिवेदन, चिकित्सा परीक्षण प्रतिवेदन और प्रमाण-पत्र अपलोड करने में विलम्ब हुआ था। इसके अलावा, अदालतों के समक्ष दत्तक ग्रहण याचिका दायर करने में और संभावित दत्तक माता-पिता की गृह अध्ययन प्रतिवेदन अपलोड करने में महीनों का विलंब हुआ था। बच्चों को गोद लेने के लिए स्वतंत्र घोषित करने में विलम्ब से उनके गोद लेने की संभावना कम हो गई। अधिकांश मामलों में एसएए द्वारा दत्तक-ग्रहण के बाद अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी जिसके कारण इस बात का आश्वासन नहीं था कि गोद लिए गए बच्चों की देखभाल की जा रही है। सरकार ने 'प्रायोजन' और 'पालक देखभाल' योजनाओं को भी लागू नहीं किया जिसके कारण परिवार के वातावरण में बच्चों की वृद्धि और विकास हासिल नहीं किया जा सका, खासकर उन मामलों में जहां परिवार/रिश्तेदार और अन्य व्यक्ति बच्चों की मदद करने के इच्छुक थे लेकिन आर्थिक तंगी के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे हैं।

एक बच्चे के लिए सबसे अधिक वांछनीय स्थिति अपने माता-पिता के साथ रहने में होती है जहां बच्चा उनकी देखभाल में सुरक्षित महसूस करता है। इसलिए, सरकार के लिए यह जरूरी है कि बच्चे को उसके परिवार के साथ रखने के लिए हर संभव प्रयास करे और केवल उन परिस्थितियों में जहां यह बच्चे के सर्वोत्तम हित में नहीं है या संभव नहीं है, अन्य विकल्प जैसे कि उन्हें सीसीआई में रखने या गोद लेने आदि पर विचार किया जाना चाहिए।

बच्चों का पुनर्वास संस्थागत देखभाल और परिवार आधारित गैर-संस्थागत देखभाल यानी दत्तक ग्रहण, पालन-पोषण और प्रायोजन के माध्यम से किया जाता है। इनमें से, अनाथ और परित्यक्त/समर्पण किए गए बच्चों के लिए सबसे अच्छा परिदृश्य उनका दत्तक ग्रहण करना होगा, क्योंकि गोद लेने से बच्चा कानूनी रूप से सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों और ज़िम्मेदारीयों के साथ माता-पिता का एक नया समूह प्राप्त करता है, जो इस रिश्ते से जुड़े होते हैं। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 56 उपबंध करता है कि अनाथों और परित्यक्त एवं आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों के लिए परिवार का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए गोद लेने का सहारा लिया जाएगा।

आईसीपीएस दिशानिर्देश प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (एसएआरए) के गठन हेतु, गोद लेने के कार्य का समन्वय, निगरानी

और विकास करने, ज़िला स्तर पर डीसीपीयू के साथ संपर्क करने और गोद लेने के लिए सीडब्ल्यूसी को तकनीकी सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है।

विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी (एसएए) सीडब्ल्यूसी के आदेश द्वारा वहां रखे गए अनाथों, परित्यक्त और आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों को गोद लेने के उद्देश्य से एक चाइल्ड कैअर संस्थान है। गोद लेने की प्रक्रिया **चित्र 6.1** में दी गई है।

चित्र 6.1: गोद लेने की प्रक्रिया

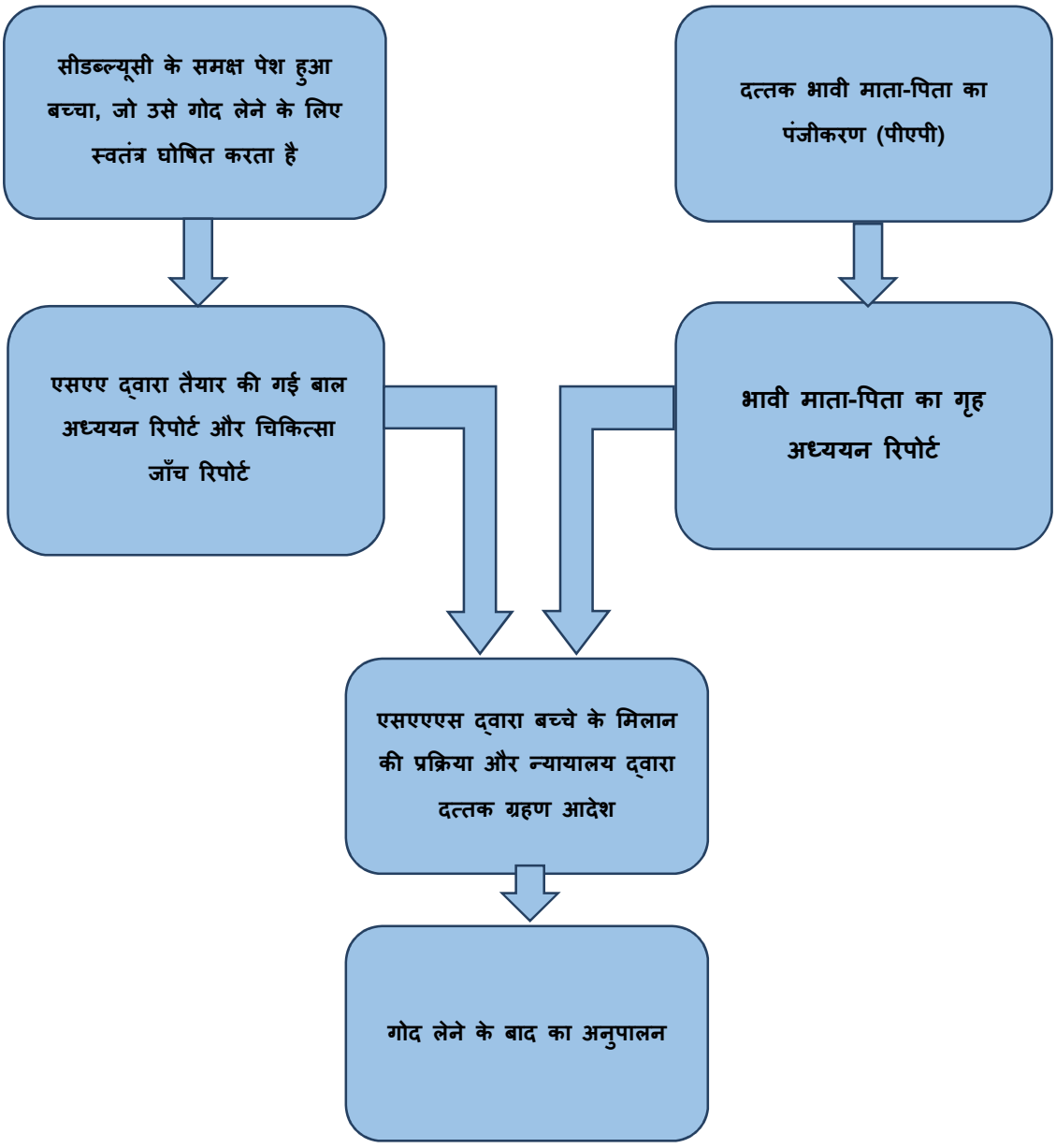

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 यह उपबंध करता है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक या अधिक संस्थानों या संगठनों को एसएए के रूप में मान्यता देगी। लेखापरीक्षा ने देखा कि 10 ज़िलों में से दो[18] में किसी भी एसएए को मान्यता नहीं

[18] पूर्वी जिला और उत्तर-पूर्वी जिला।

दी गई थी। इस प्रकार, इन दो ज़िलों में अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों को गोद लेने की सुविधा के लिए कोई समर्पित तंत्र नहीं था।

शेष आठ ज़िलों में, कुल 9 एसएए थे, जिनमें से एक[19] सरकार द्वारा चलाया जाता है, तीन[20] सरकार द्वारा सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों द्वारा, और शेष पांच गैर सरकारी संगठनों द्वारा स्वयं चलाए जाते हैं। सरकार द्वारा सीधे या सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से चलाए जा रहे चार एसएए में से, लेखापरीक्षा ने दो एसएए के अभिलेखों की जांच की और संयुक्त भौतिक सत्यापन किया।

जैसा कि सीडब्ल्यूसी द्वारा बच्चों को गोद लेने के लिए स्वतंत्र घोषित करने में विलम्ब से संबंधित पैराग्राफ में पहले ही उल्लेख किया गया है, इस प्रक्रिया में विलम्ब से बच्चों के गोद लेने की संभावना कम होने के अलावा सीसीआई में बच्चों के रहने की अवधि बढ़ जाती है। इसलिए, बच्चों को सर्वोत्तम संभव देखभाल प्रदान करने के लिए, सरकार को गोद लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है ताकि प्रक्रिया में विलम्ब से बचा जा सके। हालांकि, जाँच किए गए दो एसएए के अभिलेखों से, लेखापरीक्षा ने विभिन्न चरणों में विलम्ब देखा, जैसा कि निम्नलिखित पैराग्राफों में वर्णित है:

6.1 बच्चे को गोद लेने के लिए स्वतंत्र घोषित करने वाले सीडब्ल्यूसी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र को अपलोड करने में देरी

दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के विनियम 29 (1) (डी) में कहा गया है कि एसएए बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली *(केयरिंग्स)* में बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित करने वाली बाल कल्याण समिति द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र की प्राप्ति से 48 घंटे के भीतर अपलोड करेगा। लेखापरीक्षा ने देखा कि एसएए, पालक देखभाल एवं दत्तक ग्रहण सेवा केंद्र, निर्मल छाया कॉम्प्लेक्स ने 14 में से 6 बच्चों के संबंध में बच्चों को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित करने वाले प्रमाण-पत्र 14 से 88 दिनों के विलम्ब के बाद और दो मामलों में 496 और 625 दिनों की देरी के बाद अपलोड किया।

अपने जवाब में, डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि सीडब्ल्यूसी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र को अपलोड करने में विलम्ब अनाथ, परित्यक्त और लापता बच्चों आदि के विज्ञापनों के प्रकाशन में विलम्ब के कारण है। जवाब स्वीकार्य

[19] फोस्टर केयर एंड एडॉप्शन सर्विस सेंटर (एसएए) जेल रोड, नई दिल्ली।

[20] मातृ छाया, पहाड़गंज; बच्चों के लिए कल्याण गृह, सरिता विहार; और आश्रय अनाथालय, पीरागढ़ी।

नहीं है क्योंकि ये गतिविधियां सीडब्ल्यूसी द्वारा बच्चे को गोद लेने के लिए स्वतंत्र घोषित करने का प्रमाण-पत्र जारी करने से पहले की जाती हैं।

6.2 बाल अध्ययन प्रतिवेदन और चिकित्सा जांच प्रतिवेदन अपलोड करने में विलम्ब

दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के विनियम 7 (18) में प्रावधान है कि आत्मसमर्पण करने वाले बच्चे की बाल अध्ययन प्रतिवेदन (सीएसआर) और चिकित्सा जाँच प्रतिवेदन (एमईआर) सीडब्लयूसी द्वारा बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित करने की तिथि से दस दिनों के भीतर *केयरिंग्स* में एसएए द्वारा तैयार और पोस्ट की जाएगी। लेखापरीक्षा ने देखा कि पांच बच्चों के सीएसआर और एमईआर 23 से 195 दिनों की विलम्ब के बाद अपलोड किए गए और दो मामलों में 396 और 813 दिनों के बाद तथा 10 बच्चों के लिए अपलोड ही नहीं किया गया था।

अपने जवाब में डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि सीएसआर और एमईआर, एसएए अधिकारियों द्वारा डॉक्टर सहित विभिन्न अन्य अधिकारियों के परामर्श से तैयार किया जाता है, जिसमें समय लगता है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित मामलों में डीडब्ल्यूसीडी द्वारा कोई विशिष्ट जवाब नहीं दिया गया। तथ्य यह है कि प्रतिवेदन अपलोड करने में विलम्ब हुआ और ऐसे मामले भी थे जहां इन्हें बिल्कुल भी अपलोड नहीं किया गया था। इसके अलावा, विनियमों में 10 दिनों का निर्दिष्ट समय नियमित कारकों को ध्यान में रखते हुए रखा गया होगा।

6.3 भावी दत्तक माता-पिता की गृह अध्ययन प्रतिवेदन अपलोड करने में विलम्ब

दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के विनियम 9 (10) में प्रावधान है कि संभावित दत्तक माता-पिता (पीएपी) की गृह अध्ययन प्रतिवेदन (एचएसआर) को *केयरिंग्स* में दस्तावेज जमा करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि 12 मामलों में, 20 पीएपी (96 में से) का संचालन एचएसआर एसएए, सरिता विहार द्वारा 29 से 99 दिनों के विलम्ब से और आठ मामलों में 100 से 196 दिनों का विलम्ब हुआ। इसी प्रकार, 27 मामलों में, 40 पीएपी (79 में से) का एचएसआर निर्मल छाया द्वारा 16 से 87 दिनों का विलम्ब और 13 मामलों में 115 से 202 दिनों का विलम्ब हुआ। केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पीएपी से शुल्क भी वसूल नहीं किया गया जिससे सरकारी खजाने को ₹ 4.74 लाख की हानि हुई।

डीडब्ल्यूसीडी ने अपने जवाब में कहा (दिसंबर 2021) कि महामारी के कारण और यहां तक कि वर्तमान में भी, पीएपी अपने निवास स्थान पर भौतिक दौरे के लिए तैयार नहीं हैं, या जांच के समय खुद को उपलब्ध नहीं कराते हैं। आगे यह भी कहा गया कि *केयरिंग्स* पोर्टल पर एचएसआर को अंतिम रूप से अपलोड करने से पहले वर्चुअल सत्यापन दो या तीन बार किया जाना है। निर्मल छाया में एसएए एक सरकार द्वारा संचालित संस्थान है, जिसमें पीएपी से एचएसआर शुल्क नहीं लिया जाता है।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित प्रतिवेदन अपलोड करने में विलम्ब, महामारी से पहले की अवधि से संबंधित है। इसके अलावा, किशोर न्याय अधिनियम और दत्तक विनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी पीएपी से शुल्क वसूल किया जाना है।

6.4 न्यायालय के समक्ष दत्तक ग्रहण याचिका दाखिल करने में विलम्ब

दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के विनियम 12(1) में प्रावधान है कि दत्तक माता-पिता द्वारा बच्चे की स्वीकृति की तारीख से 10 कार्य दिवस के भीतर एसएए न्यायालय के समक्ष दत्तक ग्रहण याचिका दायर करेगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि नमूना जांच किए गए 24 मामलों (58 प्रतिशत) में से 14 में, एसएए, सरिता विहार ने 32 से 92 दिनों के विलम्ब से न्यायालय के समक्ष दत्तक-ग्रहण याचिकाएं दाखिल कीं। एसएए निर्मल छाया के संबंध में, 14 बच्चों में से तीन[21] बच्चों को पीएपी द्वारा आरक्षित किया गया था, हालांकि, एसएसए ने इन बच्चों के संबंध में पीएपी द्वारा स्वीकार किए जाने के बावजूद दत्तक ग्रहण याचिका दायर नहीं की थी, इनमें से सबसे पुराना मामला नवंबर 2019 का है।

अपने जवाब में, डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि हालांकि दस्तावेज तैयार थे, पर संबंधित दत्तक ग्रहण न्यायालय में आवेदन दायर नहीं किया जा सका क्योंकि कोविड -19 लॉकडाउन के कारण संबंधित अवधि के दौरान न्यायालयों के कामकाज को निलंबित कर दिया गया था। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नौ मामले कोविड-19 लॉकडाउन से पहले की अवधि (सितंबर 2017 और नवंबर 2019 के बीच) से संबंधित हैं।

अनुशंसा सं. 11: विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियां, संभावित माता-पिता की अध्ययन प्रतिवेदन और गोद लेने के लिए बच्चों के विवरण सहित आवश्यक जानकारी समय पर प्रासंगिक वेब पोर्टल में अपलोड करें और बिना किसी विलम्ब

[21] स्वीकृति की तिथियाँ हैं 22.11.2019, 27.08.2020 और 27.01.2021

के न्यायालय के समक्ष गोद लेने की याचिका दायर करें। विलम्ब के लिए ज़िम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

6.5 दत्तक-पश्चात अनुवर्ती प्रतिवेदन तैयार करने में विलम्ब

दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के विनियम 13(1) में प्रावधान है कि एसएए जिसने गृह अध्ययन प्रतिवेदन तैयार की है, दत्तक-पूर्व पालक नियोजन की तारीख से दो वर्ष के लिए छः मासिक आधार पर दत्तक-ग्रहण पश्चात अनुवर्ती प्रतिवेदन तैयार करेगा। भावी दत्तक माता-पिता, और बच्चे की तस्वीरों के साथ इसे *केयरिंग्स* में अपलोड करें। इसके अलावा, विनियम 29(6)(सी) (VII) में यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक एसएए प्रत्येक बच्चे की केस फाइल में पोस्ट-प्लेसमेंट प्रगति प्रतिवेदन रखेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एसएए, निर्मल छाया द्वारा जनवरी 2013 और जुलाई 2021 के बीच 59 बच्चों के लिए 150 अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने थे, तथापि, 44 बच्चों के संबंध में कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी। शेष 15 बच्चों के संबंध में 57 छमाही दत्तक पश्चात अनुवर्ती कार्रवाई में से केवल 19 अनुवर्ती कार्रवाई किए गए। इसके अतिरिक्त, अनुवर्ती प्रतिवेदनों को भी संबंधित मामले की फाइलों में नहीं रखा गया था। अनुवर्ती कार्रवाई के अभाव में, एसएसए निश्चित नहीं कर सका कि क्या बच्चों की पर्याप्त देखभाल की जा रही है और दत्तक माता-पिता द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा रहा था।

अपने जवाब में, डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि कोविड-19 लॉकडाउन और प्रतिबंधित आवागमन के कारण, अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भौतिक दौरा नहीं किया जा सका, हालांकि, टेलीफोनिक संपर्क के माध्यम से अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की गई थी।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिसंबर 2019 से पहले की अवधि से संबंधित 44 मामलों में भी पोस्ट एडॉप्शन फॉलो-अप आयोजित नहीं किया गया था।

6.6 बच्चों को दत्तक ग्रहण के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित करने में विलम्ब

दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 का नियम 6 में बच्चों को गोद लेने से संबंधित प्रक्रिया का प्रावधान है यह पता लगाने के लिए कि क्या बच्चा परित्यक्त, अनाथ या लापता है और जैविक माता-पिता या कानूनी अभिभावकों आदि की न मिलने की स्थिति के संबंध में स्थानीय पुलिस से रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देना शामिल है। दत्तक ग्रहण विनियम, 2017, यह भी प्रदान करता है कि सीडब्ल्यूसी को एक परित्यक्त या अनाथ बच्चे को क्रमशः

दो या दो वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के मामले में सीडब्ल्यूसी के समक्ष बच्चे को पेश किए जाने की तारीख से दो या चार महीने की समाप्ति के बाद गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित करना आवश्यक है। लेखापरीक्षा ने देखा कि 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान, 36[22] बच्चों को तीन से 64 महीने के विलम्ब के बाद गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित किया गया था। बच्चों को गोद लेने के लिए स्वतंत्र घोषित करने में विलम्ब होने से उन्हें सीसीआई में लंबे समय तक रहने के अलावा माता-पिता की देखभाल वाले परिवार का हिस्सा बनने का मौका नहीं मिला। इसके अलावा, बच्चे को गोद लेने की संभावना, उम्र बढ़ने के साथ कम इसलिए अनिवार्य है कि बच्चे को सीडब्ल्यूसी द्वारा स्वतंत्र घोषित करने में विलम्ब न हो।

अपने जवाब में, डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि गोद लेने के उद्देश्य से एक बच्चे को कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित करने की प्रक्रिया के लिए विभिन्न हितधारकों अर्थात् केस हिस्ट्री और सामाजिक जांच के लिए ज़िला बाल संरक्षण इकाई, आयु निर्धारण के लिए चिकित्सा अधिकारी/बोर्ड से अनुपालन की आवश्यकता होती है, जिसके कारण विलम्ब होती है। आगे कहा गया कि इस प्रक्रिया को अब सुव्यवस्थित कर दिया गया है और बच्चों को समय पर कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित किया जा रहा है।

6.7 'प्रायोजन' और 'पालक देखभाल' के लिए योजनाएं

किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के नियम 24 के अनुसार, राज्य सरकार एक प्रायोजन कार्यक्रम तैयार करेगी। "प्रायोजन" का अर्थ है बच्चे की चिकित्सा, शैक्षिक और विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए परिवारों को पूरक सहायता, वित्तीय या अन्य प्रावधान। प्रायोजन कार्यक्रम डीसीपीयू द्वारा कार्यान्वित किया जाना था जिसके तहत बच्चों को प्रायोजित करने में रुचि रखने वाले व्यक्तियों या संगठनों का एक पैनल प्रदान करना था। यह योजना रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा अभी लागू नहीं की गई।

इसके अलावा, किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के नियम 23 के अनुसार, देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को पालक देखभाल में रखा जा सकता है, और डीसीपीयू एक जिले में पालक देखभाल कार्यक्रम को लागू करने के लिए नोडल प्राधिकरण होगा। "पालक देखभाल" का अर्थ है बच्चे के जैविक परिवार के अलावा, परिवार के घरेलू वातावरण में वैकल्पिक देखभाल के उद्देश्य से समिति द्वारा बच्चे का रखरखाव। लेखापरीक्षा ने देखा कि डीडब्ल्यूसीडी ने पालक देखभाल योजना को भी लागू नहीं किया।

[22] सीडब्ल्यूसी-II, लाजपत नगर (15) और सीडब्ल्यूसी-V, दिलशाद गार्डन (21)

इन योजनाओं को लागू नहीं करने के कारण, पारिवारिक वातावरण में बच्चे की वृद्धि और विकास नहीं हो सका, विशेषकर ऐसे मामलों में जहां परिवार/रिश्तेदार और अन्य व्यक्ति बच्चों की मदद करने के इच्छुक थे, लेकिन वित्तीय बाधाओं के कारण ऐसा करने में असमर्थ रहे। इन योजनाओं को लागू करने से, पुनर्वास उपायों के माध्यम से, सीसीआई संस्थान से बच्चों को बहाल करने में भी आसानी होगी।

अपने जवाब (दिसंबर 2021) में, डीडब्ल्यूसीडी ने लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार किया और कहा कि एसओपी और दिशानिर्देश जून 2021 में जारी किए गए हैं और विज्ञापन के साथ वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं, जिसमें उपयुक्त व्यक्ति/पालक माता-पिता और उपयुक्त सुविधा/समूह की मान्यता के लिए आवेदन मांगे गए हैं।

अनुशंसा सं. 12: प्रायोजन योजना और पालक देखभाल योजना को प्रभावी, कुशल और समय पर कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। गोद लिए गए बच्चों के लिए अनुवर्ती कार्रवाई निश्चित समय के अनुसार की जानी चाहिए।

नई दिल्ली
दिनांकः 02 फरवरी 2023

(अमन दीप चड्ढा)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांकः 14 फरवरी 2023

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक